बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 134

किराये की अड़चन

शहरी भारत में आवासीय बाजार की हालत खराब है। बहुत कम घर ही किराये के लिए उपलब्ध हैं और बिक्री के लिए उपलब्ध घरों की कीमतें बाजार से ऊपर हैं। नतीजतन भारतीय आवासीय बाजार में मांग पूरी न होने और खाली पड़े घरों की स्थिति साथ-साथ मौजूद है। आर्थिक समीक्षा 2018 में यह अनुमान जताया गया था कि अकेले मुंबई में ही करीब पांच लाख घर खाली पड़े हुए हैं जबकि दिल्ली और बेंगलूरु में करीब तीन लाख घरों के खाली रहने का अनुमान था। शहरी भारत के कुल घरों में से करीब 12 फीसदी घरों में कोई नहीं रह रहा है जबकि घर खरीदने या किराये पर लेने की चाहत रखने वाले करोड़ों परिवारों को मनमाफिक घर नहीं मिल रहे हैं। आर्थिक समीक्षा में इस संरचनात्मक समस्या के लिए 'अस्पष्ट संपत्ति अधिकारों, अशक्त अनुबंध प्रवर्तन और निम्न किराया प्रतिफल' को दोषी ठहराया गया था। मालिक अपने घरों को किराये पर देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि कानूनी ढांचा किरायेदार के पक्ष में झुका हुआ है और किरायेदार के मकान खाली करने से इनकार करने पर पूंजी की विनाशकारी क्षति होने की भी आशंका होती है। इसी वजह से घर का मालिकाना हक रखना महंगा पड़ता है क्योंकि मकान के किराये से होने वाली आय उसे गिरवी रखने पर मिलने वाली कीमत से काफी कम होती है। यह स्थिति एक घर को किराये पर चढ़ाने से हतोत्साहित करती है। दूसरे शब्दों में, समुचित एवं भरोसेमंद अनुबंध व्यवस्था नहीं होने से आवासीय बाजार में गिरावट की स्थिति पैदा हुई है।

इस दीर्घकालिक समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वादा किया है कि केंद्र सरकार किरायेदारी कानून का मॉडल विधेयक लेकर आएगी और उसे राज्यों को भेजेगी। इस विधेयक में काफी कुछ ऐसा है जो भारत के आवासीय बाजार की उलझी गुत्थियों को सुलझा सकता है। सबसे अहम काम किरायेदार एवं मकान मालिक दोनों के लिए परेशानी पैदा करने वाली संभावनाएं कम करना है। मसलन, इस मॉडल विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो प्रतिकूल हालात में भी किरायेदार की बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं न रोकने की बात करता है। अमूमन यह देखा जाता रहा है कि मकान मालिक घर खाली कराने के लिए बिजली-पानी की आपूर्ति काटने का तरीका अपनाते हैं। मकान मालिक लीज अवधि के बीच में किराया नहीं बढ़ा सकेगा और उसे मकान खाली कराने के तीन महीने पहले नोटिस भी देना होगा। इसी तरह मकान मालिक को भी राहत देने का जिक्र है। अगर किरायेदार तय अवधि से अधिक समय तक रहता है तो उसे मकान मालिक को अधिक भुगतान करना होगा। लीज के बाद के पहले दो महीनों के लिए किराया दोगुना हो जाएगा और उसके बाद वह चार गुना तक हो जाएगा।

अहम सवाल है कि क्या ऐसे किसी कानून को समुचित ढंग से लागू किया जा सकता है और क्या किराये संबंधी विवादों को न्याय प्रणाली के जरिये समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सकता है? भारत में अनुबंध प्रवर्तन से जुड़ी समस्या असल में अनुबंध की शर्तों की न होकर न्याय व्यवस्था में मुकदमों की भारी भीड़ है। इस वजह से किसी मकान पर कब्जे का विवाद उस संपत्ति की उपयोग अवधि से भी लंबा खिंच जाता है। मसौदा विधेयक किराये संबंधी विवादों के निपटारे के लिए नई अदालत बनाने की बात करता है। हालांकि ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी समर्पित अदालतों का पिछला अनुभव मिला-जुला ही रहा है। ऐसी स्थिति में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए स्वतंत्र नियामक एवं प्राधिकरण बनाने का विचार कहीं बेहतर है। समस्या विवाद-निपटान की क्षमता का है और सरकार को प्राथमिकता देते हुए उसका हल निकालना चाहिए। अगर इसमें सफलता मिलती है तो सबसे अड़ियल समस्याओं में से एक के समाधान की राह खुल जाएगी।

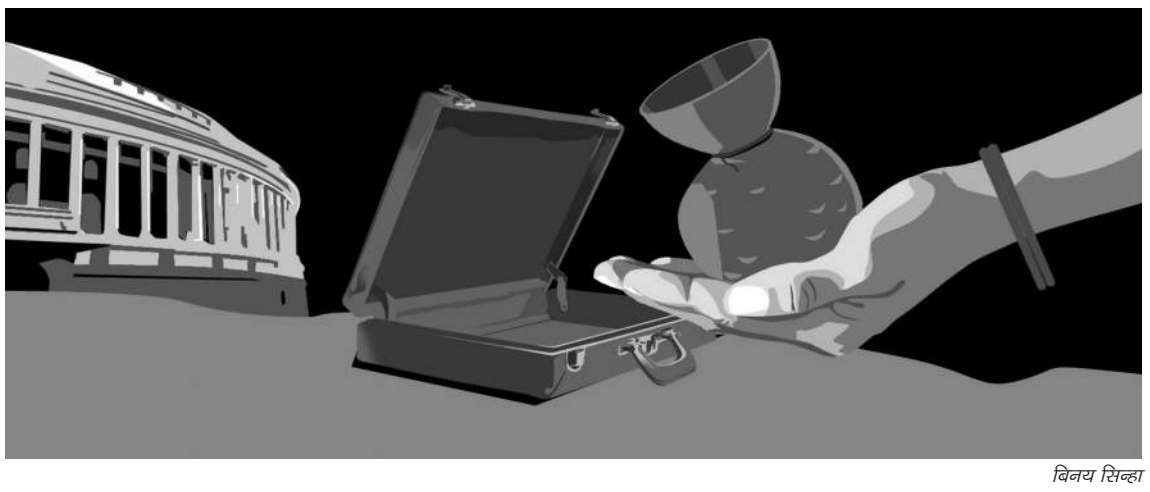

बिनय सिन्हा

खुशहाली का बढ़ना हो बजट का पैमाना

जीवन स्तर संबंधी तमाम सूचकांकों में भारत की स्थिति काफी खराब है। भारत बजट निर्माण में खुशहाली स्तर बढ़ाने को मानदंड बनाकर स्थिति सुधार सकता है। बता रहे हैं पार्थसारथि शोम

पिछले दिनों पेश आम बजट परंपरागत ढांचे वाला है। हाल ही में न्यूजीलैंड में पेश वार्षिक बजट एक खुशहाली मसौदे के अनुरूप तैयार किया गया था। यह एक नई राह दिखाने वाली कोशिश है। न्यूजीलैंड ने इस बजट के संकल्पनात्मक आधार एवं वैश्विक दृष्टि के तौर पर 'सर्वसमावेशी दार्शनिक नजरिया' अपनाया है। इसने खुशहाली आंकने के लिए जीवन-स्तर प्रारूप (एलएसएफ) में समाहित संकेतकों का इस्तेमाल किया है। उसने खुशहाली के मानक माने जाने वाले संकेतकों के लिए तकनीकी परिभाषाओं एवं श्रमसाध्य आंकड़ों के लिए ध्यान से जुटाई जानकारी भी इस्तेमाल की है। न्यूज़ीलैंड ट्रेजरी के टोनी बर्टन ने सरकार की जीवन-स्तर पर जारी रिपोर्ट 'ऑवर पीपल, ऑवर कंट्री ऐंड ऑवर फ्यूचर' के संदर्भ में हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में ये बातें कहीं।

व्यक्तिगत खुशहाली की तेजी से उभरी संकल्पना बड़ी तेजी से फैली है। इसमें समग्र जीवन संतुष्टि के साथ जीवन की सार्थकता का अहसास भी शामिल है। यह आराम एवं मौजमस्ती में व्यतीत किए जाने वाले समय और उसकी गुणवत्ता के रूप में प्रदर्शित होता है। लोग अपना खाली समय किस तरह व्यतीत करते हैं? भारत की निम्न खुशहाली रैंकिंग को देखते हुए क्या भारत को भी अपने भविष्य के अपने बजट में खुशहाली परिप्रेक्ष्य अपनाने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसा होने पर बजट निर्माण प्रक्रिया के दौरान भारत की मौजूदा चुनौतियां नजर आने लगेंगी। वैसे भी अब भारतीय बजट में गोपनीयता की उपयोगी भूमिका नहीं रह गई है।

ऐसा मकसद हासिल करने के लिए हमें एलएसएफ और उसके साधनों के प्रति न्यूज़ीलैंड के नजरिये का परीक्षण करने की जरूरत है। एलएसएफ का सामाजिक आधार नागरिकों की संलिप्तता और शासन का आश्वासन है। बेहतर शासन का पता इससे चलता है कि आबादी का कितना अनुपात भेदभाव की शिकायत करता है और कोई समूह अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में कितना सफल रहता है? भारत में भी खुशहाली मानक वाले बजट को अपनाने के लिए यह एक समुचित मानक होगा।

न्यूज़ीलैंड ने 2019 के अपने बजट में जो पांच प्राथमिकताएं तय की हैं उनमें एक टिकाऊ एवं निम्न उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था, डिजिटल भागीदारी, माओरी एवं प्रशांत क्षेत्र की आय एवं कौशल बढ़ाना, बाल गरीबी एवं पारिवारिक हिंसा में कटौती और बच्चों की खुशहाली बढ़ाने के साथ ही मानसिक सेहत संवर्द्धन शामिल हैं। इन सभी प्राथमिकताओं को मापन-योग्य मानदंडों में बांटा भी गया था।

जीवन-स्तर मसौदे में चुनिंदा सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय मानदंडों के संदर्भ में, पर्यावरण की गुणवत्ता एक केंद्रीय चिंता है। इसमें वैज्ञानिक रूप से दर्ज वायु गुणवत्ता, संतोषजनक जल गुणवत्ता और बस्ती के एक किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक परिवेश आता है। जन्म के समय शिशु की जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य की स्थिति, रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली मुश्किलें और खराब मानसिक सेहत से गुजर रही आबादी का अनुपात भी इन मानदंडों में शामिल हैं। आवास भी एक मानक है जिसमें प्रति व्यक्ति कमरों की उपलब्धता, घर की लागत का बोझ और आवास की गुणवत्ता जैसे बिंदु हैं। वयस्कों की शिक्षा और 15 साल की उम्र तक संज्ञानात्मक कौशल का स्तर भी मानदंड बनाया गया है।

आय एवं उपभोग जैसे वृहद आर्थिक मानदंडों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया था। लोगों की सभी स्रोतों से प्राप्त खर्च-योग्य आय, खर्च की मात्रा और उनके पास उपलब्ध भौतिक वस्तुओं को भी जगह दी गई। रोजगार एवं आय मानदंड के तहत बेरोजगारी दर, रोजगार दर, माध्य प्रति घंटा आय, काम के दौरान हादसों की दर और नौकरी पर तनाव जैसे बिंदु समाहित हैं।

इस बजट प्रक्रिया में सामाजिक हालात को भी मानदंड बनाया गया। प्रति एक लाख आबादी पर हत्या की अंतरराष्ट्रीय दर, पीड़ित बताए जाने की घटनाएं और सुरक्षा को लेकर लोगों की भावना को भी मानक बनाया गया। सामाजिक संपर्क में सामाजिक नेटवर्क का सहयोग, अकेलापन और सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत समय शामिल हैं। बच्चों एवं बिना बच्चों वाले दंपतियों से संबंधित आंकड़ों को भी इसमें जगह दी गई।

हालांकि जीवन-स्तर मसौदा कोई स्थिर प्रारूप नहीं है। यह इस बात को मानता है कि 'चार तरह की पूंजी' की वृद्धि, वितरण एवं स्थायित्व का अंतरराष्ट्रीय खुशहाली पर प्रभाव होता है। ये चार पूंजी हैं- प्राकृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, मानव पूंजी एवं वित्तीय एवं भौतिक पूंजी। प्राकृतिक पूंजी में जमीन, मिट्टी, पानी, पेड़-पौधे और जानवर जैसे प्राकृतिक पर्यावरण वाले पहलू आते हैं। सामाजिक पूंजी के तहत विश्वास, कानून का शासन, सांस्कृतिक पहचान, लोगों एवं समुदाय के बीच संपर्क और समाज को सहारा देने वाले मानदंड एवं मूल्य आते हैं। न्यूज़ीलैंड के मूल निवासियों माओरी की संस्कृति का संरक्षण भी इसमें अंतर्निहित है। मानवीय पूंजी में लोगों की दक्षता, ज्ञान, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जैसे पहलू समाहित हैं जो लोगों को पढ़ाई, काम और मौजमस्ती के लायक बनाते हैं। वित्तीय एवं भौतिक पूंजी के अंतर्गत मकान, सड़क, इमारतें, अस्पताल, कारखाने, साजोसामान और गाड़ियां आती हैं और आय बढ़ाने एवं भौतिक जीवन स्थिति बेहतर करने में उनकी भूमिका होती है। ये सारी पूंजी अंतर्निर्भर हैं और एक साथ मिलकर खुशहाल जीवन का निर्माण करती हैं।

बजट निर्माण की यह प्रक्रिया जटिल थी। जैसे, मंत्रालयों के फैसले सरकारी प्राथमिकता निर्धारण एवं मूल्यपरक निर्णयों पर आधारित थे। आंकड़ों, विश्लेषण एवं परामर्श के जरिये सरकारी प्राथमिकताओं के बारे में सूचित किया गया और फिर पर्यावरण, सामाजिक विकास, बाल खुशहाली इकाई और वित्त जैसे कई मंत्रालयों को भी उससे जोड़ा गया। फिर उन्हें कैबिनेट समितियों एवं कैबिनेट की पूर्ण बैठक में भेजा गया जहां पर समग्र बजट रणनीति के हिसाब से अनुरूपता का परीक्षण किया गया। आखिर में कैबिनेट ने बजट प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।

हालांकि इसमें कुछ जोखिम होने की बात को भी न्यूज़ीलैंड ने माना है। सरकारी क्रियाकलापों के व्यापक दायरे के बारे में जानकारी के सीमित होने का जोखिम भी शामिल है। सेवा देने वाली सरकारी एजेंसियों से खुशहाली बढ़ाने में योगदान देने की अपेक्षा है लेकिन उनके मौजूदा कार्यों से अलग काम भी उन्हें करने पड़ सकते हैं।

निस्संदेह अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व को खुशहाली लाने वाले बजट की अहमियत पर गौर करने की जरूरत है जो व्यय आवंटन को न्यायसंगत बना सकेंगे। यह सरकारी व्यय को लेकर पीढ़ीगत स्थायित्व की दिशा का भी संकेत देंगे। देश एकपक्षीय ढंग से कदम उठा सकते हैं। भारत पर्यावरणीय स्थायित्व से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है और यहां बेहद गरीबी में जी रहे लोगों की संख्या में गिरावट भी अपेक्षित नहीं रही है। इसके अलावा भारत के सामाजिक-आर्थिक संकेतक भी संतोषजनक नहीं हैं। पिछले महीनों में आए तमाम संकेतक इस ओर इशारा करते हैं। ऐसे में सरकार को खुली एवं सहभागी परामर्श के जरिये अपनी प्राथमिकता तय करने में अधिक पारदर्शिता लाने की जरूरत है।

भारत में जीवन-स्तर प्रारूप अपनाने के लिए व्यापक कोशिश की जरूरत होगी लेकिन ऐसा किया जा सकता है। भारत में पहले से ही काफी सांख्यिकीय आंकड़े मौजूद हैं। अब नए उपकरणों वाले नजरिये एवं विवरण पर बारीक नजर रखने की जरूरत होगी। क्या भारत अगले तीन वर्षों में खुशहाली आधारित बजट पेश करने वाली पहली उदीयमान अर्थव्यवस्था बन सकता है या कम-से-कम इसकी घोषणा ही कर सकता है? ऐसा होने पर ही भारत के लोगों की खुशहाली बढ़ाने पर होने वाले सार्वजनिक व्यय की पारदर्शी ढंग से निगरानी हो सकेगी और जरूरी होने पर उसे सही किया जा सकेगा। अभी खुशहाली के तमाम मानदंडों पर निचले पायदान पर मौजूद भारत केवल इसी तरह से अपनी स्थिति में सुधार कर पाएगा।

सुविधा और निजता हनन को लेकर बड़ी उलझन

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

बेल्जियम की एक घटना ने आवाज-संचालित रोबोटिक असिस्टेंट को लेकर बढ़ती निजता की चिंता उजागर की है। एक ठेकेदार ने गूगल असिस्टेंट पर दर्ज 1,000 से अधिक ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक प्रसारक वीआरटी को भेज दीं। इन रिकॉर्डिंग में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ ही उनकी पहचान सुनिश्चित करने वाले कुछ निजी आंकड़े भी थे। इनमें से 153 बातचीत तो रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए थीं क्योंकि उनके लिए उपभोक्ताओं ने 'ओके गूगल' की मंजूरी नहीं दी थी। गूगल ने इस मामले में अपने आधिकारिक ब्लॉग पर कहा है कि ये रिकॉर्डिंग अनाम रूप में कूटबद्ध की गई थीं ताकि विशेषज्ञ विश्लेषण कर वर्चुअल असिस्टेंट को अधिक स्मार्ट बना सकें।

यह समस्या इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी। गूगल असिस्टेंट, ऐपल के सिरी और एमेजॉन के एलेक्सा का इस्तेमाल दुनिया भर में एक अरब से भी अधिक लोग करते हैं। ये वॉयस असिस्टेंट कई मायनों में हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं। उनका वजूद अपने आप में मशीन लर्निंग की जीत दिखाता है। लेकिन उन्हें भारी भरकम डेटा के जरिये 'प्रशिक्षित' किए जाने की जरूरत है। इसीलिए बातचीत रिकॉर्ड की जाती है। असिस्टेंट का प्रदर्शन सुधारने के लिए उन बातचीत को लोगों की टीम सुनती हैं और असिस्टेंट को ये संवाद अशुद्धियां होते हुए भी समझने में मदद करती हैं।

भले ही वॉयस असिस्टेंट पर होने वालीं बातचीत गुमनाम होती हैं लेकिन यह अपने-आप में निजता में दखल देने वाली बात है। एक बातचीत में कई संवेदनशील निजी जानकारियां होती हैं और उनसे उस शख्स की पहचान एवं भौगोलिक स्थिति भी पता चल जाती है। इस प्रकरण में यह बात भी सामने आई कि ये असिस्टेंट अचानक ऑन होकर बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं।

एमेजॉन के असिस्टेंट एलेक्सा के साथ भी यही होता है। उपयोगकर्ता एलेक्सा पर हुई बातचीत के ब्योरे दोबारा प्ले कर सकता है और कुछ फ्रीक्वेंसी पर रिकॉर्डिंग की यह गलती घटित होती है। जब कोई व्यक्ति 'वेकअप' शब्द बोलता है तो उसकी प्रोसेसिंग गलत हो जाती है। कभी-कभार सामान्य बातचीत या पृष्ठभूमि से आने वाली आवाज को भी मशीन वेकअप शब्द के तौर पर सुन लेती है। दरअसल किसी डिजिटल असिस्टेंट में एक माइक्रोफोन भी शामिल होता है जो हमेशा ऑन रहता है और बातें सुनता रहता है। इस प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग केवल तभी शुरू करने का प्रावधान है जब वेकअप बोला जाए। लेकिन माइक्रोफोन हमेशा चालू रहता है। अगर फोन में इसे शुरू करने के लिए एक पुश स्विच होता तो भी उपयोगकर्ता इस माइक को हमेशा ऑन ही रखते क्योंकि यह उसके काम करने के लिए बुनियादी चीज है।

इस तरह यह प्रोग्राम गलती से भी शुरू हो सकता है और यह उपयोगकर्ता के नियंत्रण में नहीं होता है। उन रिकॉर्डिंग को विश्लेषण के लिए मदर सर्वर के पास भेज दिया जाता है। इससे असिस्टेंट का प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलती है और ऐसी तकनीक के विकास के लिए यह अहम भी है। लेकिन यह प्रक्रिया असुरक्षित है। इन रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि तैयार करने एवं विश्लेषण के लिए चुने गए ठेकेदार गोपनीयता खंडित कर सकते हैं। अगर सर्वर हैक कर लिया गया तो यह पूरा डेटा गलत हाथों में पड़ सकता है।

रिकॉर्डिंग को गुमनाम ढंग से दर्ज करने से डिजिटल असिस्टेंट का प्रदर्शन खराब हो सकता है। यही वजह है कि गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा की तुलना में ऐपल के सिरी असिस्टेंट के पिछड़ जाने की शिकायत का ताल्लुक इस गुमनामी से ही है। सिरी काफी हद तक रिकॉर्डिंग को गुमनाम रखता है। इन आंकड़ों का मानव विश्लेषण भी केवल तभी होता है जब किसी खास संवाद की पहचान के लिए बेतरतीब टैग लगा हो। लेकिन इसके चलते सिरी अपने उपयोगकर्ताओं की निजी पसंद एवं मिजाज को नहीं भाप पाता है। एमेजॉन और गूगल अपने वॉयस असिस्टेंट पर दर्ज गतिविधियों को इस तरह बेचती हैं कि वे उन्हें पूरी तरह गुमनाम बनाने से हिचकती हैं। ये कंपनियां ऑनलाइन सर्च और ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजक सामग्रियों की पसंद, चिकित्सकीय स्थिति, फोन कॉल और लिखित संदेशों की प्रवृत्तियों के बारे में जानने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण कराती हैं। यहां तक कि ये डिजिटल असिस्टेंट अपने उपयोगकर्ता की आवाज के लहजे से उसकी मनोदशा एवं मानसिक स्थिति के बारे में भी सटीक अंदाजा लगा सकते हैं।

इस विश्लेषण की मदद से मुकम्मल प्रोफाइल तैयार करने में मदद मिलती है जिसे लक्षित मार्केटिंग एवं निजीकृत विज्ञापन अभियान चलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब एमेजॉन आपको आपकी पसंद के टीवी शो, फिल्में, संगीत एवं किताबों के बारे में पेशकश करता है तो आपको ये सब जादू सरीखा लगता है। इसी तरह गूगल भी उन पर्यटक स्थलों के बारे में विज्ञापन दिखाने लगता है जहां के लिए आप रुचि दिखा चुके हैं। असल में, आपकी ऑनलाइन गतिविधियों के रुझान एवं असिस्टेंट के साथ आपकी सक्रियता के विश्लेषण से यह संभव हो पाता है।

लेकिन इस सुविधा की कीमत भी चुकानी पड़ती है। उपयोगकर्ताओं को अपनी निजता गंवाने और सुविधा के बीच संतुलन साधने की जरूरत है। इसका मतलब होगा कि असिस्टेंट सेवा देने वाली कंपनी व्यापक स्तर पर पारदर्शिता दिखाए और उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा पर उसका नियंत्रण हो। लेकिन दुर्भाग्य से, अधिकांश देशों में ऐसा कर पाने वाले कानून नहीं हैं। यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण नियमन इस दिशा में अग्रदूत की भूमिका निभा रहा है लेकिन अधिकांश देशों में इतना सशक्त निजता कानून नहीं है। नतीजतन ऐसी सेवाएं देने वाली कंपनियां ही यह तय करती हैं कि वे लोगों की निजता का कितना ध्यान रखेंगी?

आतंकी राज्य के इस डिजिटल संस्करण में आपको केवल बिग बॉस ही नहीं देख रहे हैं।

कानाफूसी

सीता माता के लिए लड़ाई

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रीलंका में एक मंदिर निर्माण के वादे को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर बनाने का वादा किया था लेकिन यह योजना बनाने के स्तर से आगे नहीं बढ़ सका। धार्मिक न्यासों के प्रभारी मंत्री पी सी शर्मा ने हाल ही में कहा कि सरकार मंदिर का निर्माण कराएगी और परियोजना की शुरुआत करने से पहले एक सर्वे भी कराएगी। इस पर चौहान ने ट्वीट किया, 'कमलनाथ सरकार के अफसर श्रीलंका जाके सर्वे करके सत्यापित करेंगे कि सीता माता का अपहरण हुआ था या नहीं। मित्रों इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है।' उन्होंने राज्य सरकार पर एक 'अटल सत्य' की 'जांच' की घोषणा करके हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया।

बेमजा छुट्टियां

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शुक्रवार को सभी विभागों को भेजे गए एक आदेश में नई सरकार के पहले 50 दिन में किए गए कार्यों का ब्योरा देने के लिए कहा गया। इसके चलते अधिकारियों को सप्ताहांत में भी काम करना पड़ा। सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया है और 50 दिन के काम के बारे में जानकारी मांगने से अधिकारी चकित रह गए। वे सभी उपलब्धियों के कॉलम में जानकारियां लिखने के लिए फाइलें छान रहे थे।

आपका पक्ष

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना

देश में ऊर्जा की खपत बढ़ रही है और बढ़ती आबादी के कारण सरकार के समक्ष मांग के अनुसार पेट्रोल, डीजल तथा बिजली की आपूर्ति की चुनौती है। भारत को अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए केंद्र सरकार सौर ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत कर्क रेखा में स्थित है। इससे सूर्य की किरण प्रचुर मात्रा में मिलती है। दुनिया में 100 से अधिक देश कर्क एवं मकर रेखा के बीच में स्थित हैं जहां सूर्य की ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिलती है। इस भौगोलिक स्थिति का फायदा लेने के लिए कुल 121 देशों ने वर्ष 2015 में इंटरनैशनल सोलर अलायंस की स्थापना की। भारत में इसका मुख्यालय गुरुग्राम में निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार ने इन देशों का नाम सूर्यपुत्र रखा है। इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा का अधिकतम दोहन कर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत कोयला रहा है। इससे विदेशी मुद्रा खर्च करने के साथ वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। भारत सौर ऊर्जा पर ज्यादा जोर दे रहा है और पिछले साल दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क का लोकार्पण कर्नाटक में किया गया। अगर देश में सौर ऊर्जा कार्यक्रम सफल हो जाता है तो काफी हद तक देश को ऊर्जा संकट एवं वायु प्रदूषण से राहत मिल सकती है।

अक्षय ऊर्जा से बिजली की जरूरत पूरी कर प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

आधुनिक दिल्ली की निर्माता का जाना

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आधुनिक दिल्ली का निर्माता कहा जाता है। शीला दीक्षित के कार्यकाल में शुरू हुई योजनाएं आज पूरी हो रही हैं और उन योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। दिल्ली में मेट्रो का परिचालन हो या फ्लाईओवर का निर्माण ऐसी अधिकतर योजनाएं शीला दीक्षित के कार्यकाल में शुरू की गई थी। भारत में कॉमन वेल्थ गेम का आयोजन भी शीला के कार्यकाल में ही हुआ। इस खेल में हुए कथित घोटाले ने शीला की लोकप्रियता कम की तथा कांग्रेस की सरकार गिरने में इसका अहम योगदान भी रहा। आम आदमी पार्टी ने कॉमन वेल्थ गेम में कथित घोटाले तथा निर्भया कांड के बाद असुरक्षित दिल्ली का ऐसा माहौल बनाया जिससे 15 साल की कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। अभी हाल में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ है और इस परियोजना की शुरुआत शीला दीक्षित ने की थी। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो शीला दीक्षित के कार्यकाल में शुरू हुई थीं लेकिन उसका श्रेय आज दूसरा दल ले रहा है। दिल्ली की बढ़ती बोझ के कारण सड़कों पर अक्सर जाम लग जाता था। शीला सरकार ने फ्लाईओवर बनाकर दिल्ली को जाम से निजात दिलाई। करीब 15 साल के कार्यकाल में शीला दीक्षित ने दिल्ली को आधुनिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शीला दीक्षित का शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रविवार को शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम दर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित, भाजपा तथा आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित के अहम योगदान को दिल्लीवासी याद रखेंगे।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।